प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी पहल

भारत में 'मेक इन इंडिया' पहल ने 10 साल में व्यापक परिवर्तनकारी प्रभाव छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ने विनिर्माण को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा प्रदान कर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पीयूष गोयल
(लेखक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं)

भारत में 'मेक इन इंडिया' पहल ने 10 साल में व्यापक परिवर्तनकारी प्रभाव छोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण ने विनिर्माण को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा प्रदान कर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 25 सितंबर को देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'गेम-चेंजिंग' पहल 'मेक इन इंडिया' के दस साल पूरे किए। इसने रोजगार सृजन तथा निवेश बढ़ाने के माध्यम से भारत का औद्योगिक परिवेश महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इसने सामान्य नागरिकों में विश्वास पैदा किया है। इस पहल ने उनमें यह विश्वास भी पैदा किया है कि वे संपत्ति सृजन करने वाले बन सकते हैं। 'मेक इन इंडिया' की दस साल की यात्रा बहुत उल्लेखनीय रही है जिसने औद्योगिक क्षेत्रों में नया उत्साह पैदा किया है और ये देश की अर्थव्यवस्था के विकास इंजन बन गए हैं। इस पहल ने घरेलू मांग पूरी करने के साथ ही निर्यात में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस उत्साहवर्धक यात्रा की शुरुआत ऐसे कठिन समय में हुई थी जब घरेलू निवेशक निराश थे।

उनकी इस निराशा का कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अक्षम कांग्रेस सरकार का खराब प्रशासन तथा 'नीतिगत निष्क्रियता' थी। उस समय अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी और लोगों का उसके प्रति विश्वास खत्म हो गया था। उस समय मीडिया की सुर्खियां लगातार भ्रष्टाचार घोटालों से भरी रहती थीं, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही थी, ब्याज दरें ऊंची थीं तथा भारतीय मुद्रा रुपये का भविष्य अनिश्चित लग रहा था। इस निराशाजनक व अंधकारमय भावना को समाप्त करने के लिए भारत के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में निर्णायक मत दिया था। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत के विकास और प्रगति का एक निर्णायक दृष्टिकोण पेश किया था। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत एक विश्व महाशक्ति बन कर उभरे। वे चाहते थे कि भारत में रोजगारों का सृजन हो और हमारे नौजवानों को अपना और देश का भविष्य बनाने का अवसर मिले। उन्होंने पहचान लिया था कि भारत को सफल बनाने के लिए विनिर्माण का क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

ऐसे समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की। यह पहल शुरू करने के बाद बीते पिछले दस साल एक उल्लेखनीय यात्रा रही है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए अन्य बहुआयामी व परिवर्तनकारी परिवर्तनों के बिना सफल न हुई होती। उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख सुधारात्मक कदमों में वस्तु एवं सेवाकर-जीएसटी, 'बैंकरप्सी कोड' तथा अनेक अन्य सुधार शामिल हैं। देश में 'बिजनेस सुगमता' सुनिश्चित करने के लिए 42,000 से अधिक नियमों का पालन समाप्त किया गया। इसके साथ ही ऐसे 3,700 प्रावधान भी समाप्त किए गए जो मामूली अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करते थे। इनको विभिन्न कानूनों और संहिताओं से हटाया गया ताकि छोटे बिजनेसों का नौकरशाही द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न समाप्त हो। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत की स्थिति विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में तेजी से सुधरी। इसके परिणामस्वरूप भारत को इस रिपोर्ट में 2019 में 63वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 2014 में यह 142वें स्थान पर था।

भारत सरकार ने नौजवान उद्यमियों द्वारा की जाने वाली खोजों और आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्टअप इंडिया' पहल शुरू की। इस पहल से अनेक रोजगार तलाशने वाले युवा स्वयं रोजगार देने वाले बन कर उभरे। इस प्रकार 'स्टार्टअप इंडिया' ने देश की आर्थिक प्रगति तथा उसका आर्थिक परिदृश्य बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पहल ने स्वीकृत 'स्टार्टअप' की संख्या में भारी वृद्धि की। इनकी संख्या इस साल जून में बढ़ कर 1,40,803 हो गई। इनसे भारत में काफी मात्रा में निवेश आया तथा 15 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ।

ये स्टार्टअप देश में खोजी इकोसिस्टम को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सफाई, अंतरिक्ष की खोज, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने, स्वास्थ्यसेवा क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने तथा महिलाओं के सशक्तीकरण जैसे क्षेत्र में सामने आने वाली गंभीर समस्याओं के उपयुक्त समाधानों पर काम कर रहे हैं। सरकार ने देश में 11 औद्योगिक कॉरिडोरों के विकास पर ध्यान दिया है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20 औद्योगिक स्मार्ट शहरों का विकास किया जा रहा है जो भारत में विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति में रीढ़ की हड्डी जैसी भूमिका निभाएंगे। इनमें से चार स्मार्ट शहर भारी मात्रा में निवेश आकर्षित कर रहे हैं। इनमें विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए ढांचागत संरचना में भारी निवेश किया जा रहा है तथा तेजी से विभिन्न कामों के लिए अनुमतियां मिल रही हैं। इन 'स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी' में 1.7 लाख करोड़ निवेश पहले ही आ चुका है जिससे 80,000 लोगों को प्रत्यक्ष तथा भारी संख्या में अन्य लोगों को परोक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार की 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव'-पीएलआई योजनाओं ने अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया है जिनमें इलेक्ट्रानिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, आटोमोबाइल, टेक्सटाइल एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र शामिल हैं। इन पीएलआई योजनाओं का उद्देश्य इन क्षेत्रों में तेजी से टिकाऊ विकास सुनिश्चित कर यह सुनिश्चित करना है कि ये वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता में सक्षम हों। पीएलआई योजनाओं के परिणामस्वरूप 1.32 लाख करोड़ निवेश प्राप्त हुआ है जिससे लगभग 11 लाख करोड़ के विनिर्माण उत्पाद सामने आए हैं। इससे प्रत्यक्ष रूप से 8.5 लाख करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जबकि परोक्ष रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या इस पहल के कारण बहुत अधिक है।

ढांचागत क्षेत्र में प्रधानमंत्री की पहलों ने भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ ही ढांचागत विकास देश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने का प्रमुख साधन बन गया है। आज भारत में एक्सप्रेसवे व हाईवे का विशाल और बढ़ता नेटवर्क मौजूद है। नए, विश्व-स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं तथा नए 'फ्रेट कॉरीडोर' सामने आ रहे हैं। भारत को लगातार निवेश के बहुत आकर्षक लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। देश वर्तमान समय में '4 डी लाभ' दे रहा है जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का निर्णायक नेतृत्व, हमारे नौजवानों, कौशल व कुशल भारतीयों का जनसंख्या लाभांश, अर्थव्यवस्था में 140 करोड़ भारतीयों द्वारा पैदा की जाने वाली मांग, निवेशों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने वाला लोकतंत्र तथा कानून का शासन शामिल हैं जो किसी एक या दूसरे के खिलाफ भेदभाव की अनुमति नहीं देते हैं। यह '4-डी' भारत में विनिर्माण आकर्षित करने का प्रमुख मामला है। आज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को यहां अपने बिजनेस बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। निवेशक समुदाय में इसके प्रति भारी उत्साह है। अनेक प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहे हैं जो भारत की प्रगति में निवेश कर उसमें साझेदार बनना चाहते हैं। दूसरे देशों की सरकारें और दुनिया भर के सीईओ भारत में अवसरों की तलाश रहे हैं। अनेक देशों ने भारत के साथ व्यापार समझौते भी किए हैं।

दुनिया अब भारत को एक विनिर्माण लक्ष्य के रूप में देख रही है। इसका एक प्रमुख कारण भारत का प्रतियोगी लाभ तथा अर्थव्यवस्था के जीवन्त मूलाधार हैं। आज मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, आर्थिक वृद्धि तेज है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कठोर राजकोषीय अनुशासन का पालन कर रही है। वर्तमान वैश्विक स्थितियों में यह अत्यधिक प्रशंसनीय है जहां टकराव व अनिश्चितता व्याप्त है। प्रधानमंत्री मोदी की पहलों ने स्थिति में अकल्पनीय परिवर्तन किया है। जहां 2014 के पहले भारत को दुनिया के 'अस्थिर पांच' देशों में माना जाता था, वहीं अब यह दुनिया के 'सर्वोच्च पांच' में शामिल है। इस प्रकार पिछले दस साल में प्रधानमंत्री मोदी की 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों ने इसे एक परिवर्तनकारी दशक बना दिया है। भारत कांग्रेस शासनकाल के 'बरबाद दशक' से निकल कर समग्र प्रगति की दिशा में लंबी छलांग लगा रहा है।